प्रेस विज्ञप्ति / Press Release **सितंबर / September 15, 2020**

राज्य में एमएसएमई पारितंत्र के विकास हेतु सिडबी का गुजरात सरकार के साथ गठबंधन

SIDBI joins hands with Government of Gujarat for the Development of MSME ecosystem in the State

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास में संलग्न एक प्रमुख वित्तीय संस्था है, ने राज्य में एमएसएमई पारितंत्र को विकसित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया है। श्री विजय रूपानी, माननीय मुख्यमंत्री, श्री एम.के.दास, आईएएस, अपर प्रमुख सचिव, (उद्योग और खदान), गुजरात सरकार और श्री वी सत्य वेंकट राव, उप प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

Small Industries Development Bank of India (SIDBI), the principal financial institution engaged in the promotion, financing and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), has entered a Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of Gujarat to develop the MSME ecosystem in the State. The MoU was signed in the presence of the Hon'ble Chief Minister of Gujarat Shri Vijay Rupani, Shri M. K. Das, IAS, Additional Chief Secretary (Industries & Mines), Government of Gujarat (GoG) and Shri V. Satya Venkata Rao, Deputy Managing Director, Small Industries Development Bank of India (SIDBI).

इस समझौते के तहत सिडबी द्वारा गुजरात सरकार के साथ एक परियोजना प्रबंध इकाई (पीएमयू) स्थापित की जाएगी। पीएमयू की भूमिका प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को डिजाइन करने की होगी जो कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा अधिकारों, अनुसंधान और विकास, एमएसएमई इकाईयों और प्रौद्योगिकी संचालित व्यवसायों / स्टार्ट-अप आदि के बीच व्यावसायिक क्षमताओं और सहयोग बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान / उसका लाभ उठाने जैसे क्षेत्रों में गुजरात सरकार द्वारा कदम उठाए जा सकते हैं। पीएमयू राज्य में एमएसएमई इकाईयों की ओर लक्षित हस्तक्षेपों, पहलों, परियोजनाओं आदि

की सुविधा प्रदान करेगा और प्रभावकारिता बढ़ाने और अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से यदि हो तो आशोधन करने के लिए सुझाव देगा।

Under the agreement, a Project Management Unit (PMU) will be deployed by SIDBI with Government of Gujarat. The role of the PMU will be to design training and capacity building programs, which may be taken up by GoG, in areas such as technology transfer, promotion of innovation, intellectual property rights, research & development, leveraging of technology / technology solutions for enhancing business capabilities and collaborations between MSMEs & technology driven businesses / startups, etc. The PMU will facilitate interventions, initiatives, projects etc. in the State targeted towards MSMEs in the State and shall suggest modifications, if any, with the objective of enhancing efficacy and removal of bottlenecks.

इस अवसर पर, सिडबी के उप प्रबंध निदेशक, श्री वी. सत्य वेंकट राव ने कहा, "राज्य सरकार के साथ निकट सहयोग बढ़ाने के लिए हमारे कार्यक्रमबद्ध दृष्टिकोण के अनुरूप, हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 10 राज्यों में समूह लोकसंपर्क कार्यक्रमों के साथ शुरुआत की है । हमने आत्म-निर्भर भारत की तैयारी के रूप में राज्यों में समूह विकास के ढांचागत पहलुओं का समर्थन करने के लिए एक समूह विकास निधि का भी प्रस्ताव किया है। 11 राज्यों में पीएमयू की स्थापना सुदृढ़ एमएसएमई पारितंत्र के लिए लक्षित है, इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञों की बाह्यस्रोतित टीम को विभिन्न रूपों में सुकेंद्रित वचनबद्धता हेतु गठित किया गया है। हमने पहले ही हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किए हैं। हम गुजरात राज्य में वित्तीय और गैर-वित्तीय मोर्चों पर सक्रिय रहे हैं और गहरी और उपयोगी सहभागिता के लिए तत्पर हैं।"

On this occasion, Shri V. Satya Venkata Rao, Deputy Managing Director of SIDBI said, "In line with our programmatic approach to foster closer cooperation with State government, we started with cluster outreach programs at 10 States in the last financial year. We have also proposed a cluster development fund for supporting the infrastructural aspects of cluster development in States as preparation for AatmaNirbhar Bharat. The setting up of PMU in 11 States is targeted at placing expert outsourced team for more focused engagement in various forms leading to a stronger MSME ecosystem. Already we have signed MoU with Haryana, Maharashtra and Rajasthan. We have been active on financial and non-financial fronts in the State of Gujarat and look forward to deeper and fruitful engagement."

यह विकासात्मक पहल, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एमएसएमई उद्यमों पर गठित यू.के. सिन्हा समिति की रिपोर्ट में दर्ज अपेक्षाओं से जुड़ी है। इससे एमएसएमई के संवर्द्धन और विकास के लिए राज्य सरकारों के साथ सिडबी की संकेंद्रित संलग्नता और बढ़ेगी। पीएमयू, राज्य में एमएसएमई उद्यमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे - पीएसबीलोन्सइन59मिनिट्स, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यथा सरकारी ई-मार्केटप्लेस आदि पर खुद की ऑनबोर्डिंग के लिए पथ-प्रदर्शन करने की प्रक्रिया भी तैयार करेगा। इसके अलावा पीएमयू, राज्य के भीतर और बाहर दोनों स्थलों की अच्छी प्रथाओं और दिशानिर्देशों की मैपिंग कर भंडार बनाने में भी संलग्न होगा और राज्य में अच्छी प्रथाओं को अपनाए जाने को सुसाध्य बनाएगा।

यह एमएसएमई के हितार्थ किए जा रहे हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा और नीतिगत अनुसमर्थन के लिए प्रतिक्रियाएं भी प्रदान करेगा।
This developmental initiative is aligned to expectations laid down in UK Sinha Committee on MSMEs set up by the Reserve Bank of India. It envisions more focused engagement of SIDBI with State Governments for MSME promotion & development. The PMU will also prepare the process for handholding MSMEs in the State for their onboarding onto digital platforms, stock exchange listing, e-commerce platforms such as Government e-Marketplace etc. Along with that, the PMU will also engage in mapping repository of good practices and guidelines both within and outside the State and facilitate adoption of good practices. It will create a framework for evaluating impact of interventions being made for the benefit of MSMEs and shall also provide inputs for policy advocacy.

सिडबी ने 11 राज्यों यथा असम, नई दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पीएमयू स्थापित करने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी की नियुक्ति की है। भागीदार राज्यों के बीच अग्रदूत के रूप में कार्य करके, सिडबी अधिक उत्तरदायी पारितंत्र के उद्भव के लिए योगदान करना चाहता है जो स्थानीय उद्योग को वाणी दे और राष्ट्र को आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभारने के संकल्प को मजबूती प्रदान करे।
SIDBI has appointed an expert agency for setting up PMUs in 11 States namely, Assam, New Delhi, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. By acting as harbinger amongst partner States, SIDBI intends to contribute to emergence of more responsive ecosystem which is Vocal for Local and strengthens nation’s resolve to emerge as AtmaNirbhar Bharat.

सिडबी के बारे में : 1990 में अपने गठन के बाद से, सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। चाहे वे पारंपरिक, छोटे घरेलू उद्यमी हों, पिरामिड के सबसे निचले स्तर के उद्यमी हों, या फिर उच्च-स्तरीय ज्ञान आधारित उद्यमी हों, सिडबी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के जीवन को विभिन्न ऋणों तथा विकास कार्यों के माध्यम से प्रभावित किया है। सिडबी 2.0 अपने साथ समावेशी, अभिनव और प्रभाव-उन्मुख संलग्नकता की दृष्टि को लेकर चल रहा है।

अधिक जानने के लिए, देखें : https://www.sidbi.in

About SIDBI: Since its formation in 1990, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental engagements. SIDBI 2.0 carries the vision of inclusive, innovative and impact-oriented engagements.

To know more, check out: https://www.sidbi.in

मीडिया संपर्क: नीलाश्री बर्मन, मोबाइल: +91 8879760249, ई मेल: neelasrib@sidbi.in
Media contact: Neelasri Barman, Mobile: +91 8879760249, E-mail: neelasrib@sidbi.in